

न्यूज टुडे

यूनेस्को के अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (यूनेस्को-IOC) ने ओडिशा के गांवों को 'सुनामी के लिए तैयार' गांव के रूप में मान्यता प्रदान की

- यूनेस्को-IOC ने इंडोनेशिया में दूसरी वैश्विक सुनामी संगोष्ठी के दौरान ओडिशा के 24 तटीय गांवों को "सुनामी के लिए तैयार" के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह मान्यता राष्ट्रीय सुनामी तैयारी मान्यता बोर्ड (NTRB) द्वारा सत्यापन के आधार पर दी गई है।
- NTRB सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम (TRRP) लागू करता है। इस निकाय में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) के वैज्ञानिक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अधिकारी शामिल हैं।
- यूनेस्को-IOC सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम (TRRP) के बारे में
 - TRRP एक स्वैच्छिक व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय-आधारित प्रयास है। यह वैश्विक तटीय क्षेत्रों में जोखिम की रोकथाम और शमन को बढ़ावा देने का कार्य करता है।
 - उद्देश्य: सुनामी जैसी आपदा से जीवन, आजीविका और संपत्ति की रक्षा करना। इसके लिए, TRRP जागरूकता और तैयारी संबंधी रणनीतियों के माध्यम से सुनामी के प्रति प्रतिरोधकता को बढ़ावा देता है।
 - कार्य-प्रणाली: इसमें लगातार मूल्यांकन के लिए 12 तैयारी संकेतक शामिल हैं, तथा एक बार मान्यता मिलने के बाद, इसे हर चार साल में नवीनीकृत किया जाता है।
- सुनामी के बारे में
 - परिभाषा: भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन या तटीय चट्टानों के गिरने की वजह से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल होती है। इसके कारण जल का विस्थापन होता है। इसके परिणामस्वरूप, ऊर्ध्वाधर विशाल लहरों की एक श्रृंखला उत्पन्न होती है, जिसे सुनामी कहा जाता है।
 - उत्पत्ति: शब्द "सुनामी" में जापानी शब्द "त्सू" का अर्थ बंदरगाह और "नामी" का अर्थ लहर होता है।
 - विशेषताएं:
 - गति: इन लहरों की गति 500 मील प्रति घंटे (mph) से अधिक हो सकती है। यद्यपि, जैसे ही ये लहरें उथले जल में प्रवेश करती हैं, तो इनकी गति 20 से 30 मील प्रति घंटे तक धीमी हो जाती है। इस दौरान इनकी तरंगदैर्घ्यता घट जाती है, जबकि ऊंचाई बढ़ जाती है।
 - सुनामी लहर की गति लहर के स्रोत की दूरी पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (ITEWC): यह लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए हिंद महासागर के 25 तटीय देशों को सुनामी संबंधी सलाह प्रदान करता है।
 - इसमें सुनामी बॉय सिस्टम का एक नेटवर्क है, जो रियल टाइम डेटा संचारित करता है।
 - INCOIS ने भारतीय तट पर ज्वार गेज स्टेशनों का एक रियल टाइम नेटवर्क स्थापित किया है।
- भारत में सुनामी के प्रबंधन पर NDMA दिशा-निर्देश लागू हैं।
- सुनामी की मॉडलिंग और मानचित्रण: इसे भारतीय तट के साथ-साथ प्रारंभिक सुनामी और तूफान महोर्मि चेतावनी प्रणाली के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया है।

रेजिंग एम्बिशन एंड एक्सलेरेटिंग डिलीवरी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट जारी की गई

- यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 29वें पक्षकारों के सम्मेलन (CoP-29) में जारी की गई है।
- इस रिपोर्ट में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ एनर्जी ट्रांजीशन, अनुकूलन एवं लचीलापन, हानि व क्षति, प्राकृतिक पूंजी तथा जस्ट ट्रांजीशन जैसे क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है।
- रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:
 - 2030 तक जलवायु कार्बाई के लिए लगभग 6.3-6.7 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष वैश्विक निवेश किए जाने की आवश्यकता है।
 - चीन के अलावा, उभरते बाजार और विकासशील देशों (EMDCs) को 2.3-2.5 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है।
 - वर्तमान में, अधिकतर निवेश भारत और ब्राजील जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित है।
 - वित्त-पोषण अंतराल को कम करने में गैर-पारंपरिक स्रोतों की भूमिका में बढ़ोतरी हुई है। गैर-पारंपरिक स्रोतों में स्वैच्छिक कार्बन बाजार, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, विशेष आहरण अधिकार आदि शामिल हैं।
 - सौर ऊर्जा की प्रौद्योगिकी लागत में गिरावट और चीन से सौर उत्पादों की आपूर्ति में भारी वृद्धि के कारण विकासशील देशों के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा हुए हैं।
 - रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें:
 - सहयोग को मजबूत करने, क्षेत्रीय निवेश योजनाओं के विकास और परियोजना पाइपलाइनों के सह-निर्माण सहित देशों को जलवायु वित्त के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
 - सार्वजनिक वित्त-पोषण: जलवायु वित्त के लिए देशों को अपने ऋण और राजकोषीय स्थिति का बेहतर प्रबंधन करना होगा। साथ ही, घरेलू संसाधन जुटाने को बढ़ावा देने के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण जैसे उपाय अपनाने होंगे।
 - निजी निवेश: देशों को पूंजी की लागत कम करने, रियायती वित्त के लिए विकल्पों का विस्तार करने, कार्बन बाजारों की क्षमता का दोहन करने आदि पर बल देना चाहिए।
 - बहुपक्षीय विकास बैंकों को जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) के हिस्से के रूप में 2030 तक ऋण देने की क्षमता को तीन गुना करने के लिए काम करना चाहिए।

जलवायु वित्त की सुविधा के लिए तंत्र

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (1991): इसका गठन जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए किया गया है।
- ग्रीन क्लाइमेट फंड (2010): इसे CoP-16 (कानकून कॉफ्रेंस) में विकासशील देशों को समर्थन देने के लिए स्थापित किया गया था।
- नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG): यह मौजूदा दौर में काफी चर्चा में है। इसका उद्देश्य 2025 के बाद विकासशील देशों को उनके जलवायु कार्यों में समर्थन देने के लिए एक नया वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना है।

पूरे भारत और विश्व में 555वीं गुरु नानक जयंती मनाई गई

- भारतीय प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें करुणा, दया और विनम्रता की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं।
 - गुरु नानक जयंती प्रथम सिख गुरु, गुरु नानक देव जी के जन्म का प्रतीक है। उन्होंने ही सिख धर्म की नींव रखी थी।
- श्री गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाएं
 - ‘इक ओंकार’: इसका अर्थ है ‘एक ईश्वर’ जो अपनी प्रत्येक रचना में निवास करता है और परम सत्य का सृजन करता है।
 - सत्यवादिता: सत्यनिष्ठापूर्ण जीवन पर जोर दिया और सत्य को जीवन का सर्वोच्च मूल्य बताया।
 - सामाजिक असमानता: सामाजिक असमानता का निरंतर विरोध किया और जाति व्यवस्था की आलोचना की।
 - धन के साधन के रूप में धर्म: उन्होंने लोगों को सचेत किया कि वे भौतिक संपत्ति को एकल करने के लिए धर्म का उपयोग न करें।
- आधुनिक समय में उनकी शिक्षाओं की प्रासंगिकता
 - समानता और भाईचारे पर जोर: उनके इन सिद्धांतों पर अमल करने से समाज में वर्तमान में बढ़ रहे लैंगिक और जातिगत भेदभाव तथा दुनिया भर में बढ़ते संघर्ष एवं युद्ध का समाधान संभव है।
 - वंड छको (जो आपके पास है उसे बाँटें): इससे ‘संपन्न और वंचित’ के बीच बढ़ती असमानता को कम किया जा सकता है।
 - किरत करो (अपना धन उचित और ईमानदारी से कमाओ): इससे भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है।
 - सरबत दा भला (सभी का कल्याण): उनकी यह शिक्षा जलवायु परिवर्तन से निपटने और पारिस्थितिक न्याय को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।

गुरु नानक देव जी (1469-1539) के बारे में

- उनका जन्म तलवंडी (पाकिस्तान में ननकाना साहिब) में हुआ था।
- उन्होंने करतारपुर (रावी नदी पर डेरा बाबा नानक) में एक केंद्र की स्थापना की थी।
- मोक्ष का उनका विचार निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं था, बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता की मजबूत भावना के साथ सक्रिय जीवन की खोज थी।
- अपनी मृत्यु से पहले, गुरु नानक ने अपने अनुयायियों में से एक ‘लेहणा’ को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था।
 - लेहणा को गुरु अंगद के नाम से जाना गया था। उन्होंने गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया था।

विश्व भर में प्रथम “ट्रांसनेशनल संगठित अपराध के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस” मनाया गया

- गौरतलब है कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प अपनाया था।
 - इस संकल्प में 15 नवंबर को “ट्रांसनेशनल संगठित अपराध (TOC) के सभी रूपों की रोकथाम और उनके खिलाफ संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस” घोषित किया गया था।
- ट्रांसनेशनल (अंतर्राष्ट्रीय) संगठित अपराध (TOC) के बारे में
 - परिभाषा: ट्रांसनेशनल संगठित अपराध वास्तव में वह संगठित अपराध है, जिसे कई देशों में बैठे अपराधियों के समन्वय से अंजाम दिया जाता है।
 - इसके तहत अलग-अलग देशों में सक्रिय व्यक्तियों के समूह या मार्केट अवैध व्यापारिक गतिविधियों की योजना बनाते हैं और उन्हें अंजाम देते हैं।
 - प्रकार/ रूप: ट्रांसनेशनल संगठित अपराध में शामिल हैं- मादक पदार्थों की तस्करी, प्रवासियों की तस्करी, मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों की तस्करी, नकली वस्तुओं की तस्करी, आदि।
 - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (2019): इस संकल्प में आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच बढ़ते गठजोड़ के बारे में चिंताओं को उजागर किया गया है। साथ ही, इसमें नीतिगत उपायों के जरिए गठजोड़ से निपटने की सिफारिश भी की गई है।
- आतंकवादियों और संगठित अपराध के बीच गठजोड़
 - आतंकवाद का वित्त-पोषण: आतंकवादियों को संगठित अपराधों को अंजाम देने से वित्तीय मदद मिलती है।
 - उदाहरण के लिए- भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विद्रोही समूह अवैध ड्रग्स व हथियारों की आपूर्ति के कूरियर बनकर धन जुटाते हैं।
 - संगठित आपराधिक समूह आतंकवादियों को सीमा पार कराने और संगठित आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने हेतु विदेशी आतंकवादी लड़ाकों को वापस लाने में सलियत होते हैं।
 - उदाहरण के लिए- दक्षिण-पूर्व एशिया से भारत में प्रवेश हेतु मोरेह और संपूर्ण चटगांव पहाड़ी क्षेत्र, विशेष रूप से बांग्लादेश के कॉक्स बाजार का इस्तेमाल किया जाता है।
 - मोरेह भारत-म्यांमार की सीमा पर मणिपुर में स्थित है।
 - जाली मुद्रा का प्रसार: उदाहरण के लिए, आतंकवादी कश्मीर के भीतर भारतीय जाली मुद्रा प्रवेश कराने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। फिर ये जाली मुद्राएं यहां से पूरे भारत में प्रसारित हो जाती हैं।

ट्रांसनेशनल संगठित अपराध से निपटने के लिए शुरू की गई पहलें

- ट्रांसनेशनल संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (2000): यह ट्रांसनेशनल संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय उपाय है।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF): यह संगठन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त-पोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है।
- इंटरपोल: यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसके 196 देश सदस्य हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए देशों की कानूनी एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।
- मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय: यह ट्रांसनेशनल संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अवैध ड्रग्स से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए कार्य करता है।

BSNL ने भारत की पहली 'डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सैटेलाइट कनेक्टिविटी' लॉन्च की

- यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सामान्य उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन केवल आपातकालीन सेवाओं और सैन्य उपयोग तक ही सीमित था।
 - कुछ वैश्विक पहलें भी D2D प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही हैं, जैसे- AST स्पेस मोबाइल, लिंक ग्लोबल, कांस्टेलेशन ग्लोबल, स्पेसएक्स-स्टारलिनक।
- डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सैटेलाइट के कार्य:**
 - सिद्धांत: अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स धरती पर मौजूद सेल टावर्स की तरह काम करती हैं। इससे पारंपरिक मोबाइलों में कनेक्टिविटी के लिए जरूरी सेल टावर्स की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
 - यह प्रौद्योगिकी जमीन पर स्थित संचार उपकरणों तक सीधे संकेत भेजने के लिए कक्षा में स्थित सैटेलाइट्स का उपयोग करती है।
 - गैर-स्थलीय नेटवर्क (NTN) प्रौद्योगिकी: यह उपकरणों और सैटेलाइट्स के बीच निर्बाध तरीके से दो-तरफा संचार को सक्षम बनाती है।
 - BSNL 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित वायसैट के जियोस्टेशनरी एल-बैंड सैटेलाइट्स का उपयोग करेगा। इससे जमीन पर स्थित सेल टावर्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस कारण से यह दुर्गम क्षेत्रों में कवरेज के लिए संचार का एक आदर्श तरीका बन जाएगा।
- इस कदम का महत्व:
 - विश्वसनीय कनेक्टिविटी:** हर मौसम में निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, चाहे मौसम कितना भी खराब हो।
 - हाई-स्पीड इंटरनेट और व्यापक कवरेज:** यहां तक कि सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी जहां सेलुलर या वाई-फाई नेटवर्क उपलब्ध नहीं हैं, वहां भी हाई-स्पीड इंटरनेट और व्यापक कवरेज मिलेगा।
 - UPI भुगतान को सपोर्ट करता है:** ग्रामीण क्षेत्रों या जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम है, उन क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल लेन-देन करने के लिए सक्षम बनाएगा।
 - आपातकालीन कॉल और SOS संदेश:** यह ऐसी आपातकालीन स्थितियों में संचार का एक विश्वसनीय स्रोत होगा, जहां सेलुलर या वाई-फाई नेटवर्क काम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए- जोखिम भरी या साहसिक यात्रा करने वाले लोगों के लिए उपयोगी।
- चुनौतियां**
 - विलंबता:** वायस कॉल और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी रियल टाइम सुविधाओं में कुछ न्यूनतम समय के लिए विलंब हो सकता है।
 - विनियामक चुनौतियां:** चूंकि D2D सेवा भौगोलिक सीमाओं को पार कर सकती है। इस कारण से दूरसंचार संबंधी विनियमों के अनुपालन में लापरवाही देखने को मिल सकती है।
 - स्पेक्ट्रम आवंटन:** निर्बाध सैटेलाइट-से-भूमि पर संचार के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ प्राप्त करना भी एक प्रमुख चुनौती है।
 - डिवाइस संगतता (compatibility):** यह सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है कि प्रौद्योगिकी अलग-अलग स्मार्टफोन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर बेहतर तरीके से काम करेगी या नहीं।
 - प्रसार संबंधी चुनौतियां:** अलग-अलग परिवेशों में सिग्नल लॉस और व्यवधान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला 'वित्त आयोग सम्मेलन' आयोजित किया

- केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 14 नवंबर को दिल्ली में "विकास के लिए हस्तांतरण" थीम पर वित्त आयोग सम्मेलन का आयोजन किया।
- राज्य वित्त आयोग (SFC) के बारे में
 - संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 243I (243आई) के अनुसार राज्यपाल को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के लागू होने के एक वर्ष के भीतर राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा।
 - कार्यकाल: राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 साल में करना होता है।
 - कार्य (मैंडेट): राज्य वित्त आयोग 243I के तहत पंचायतों और अनुच्छेद 243Y के तहत नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। वह निम्नलिखित विषयों पर राज्यपाल को सुझाव भी देता है:
 - राज्य और स्थानीय निकायों (पंचायतों/ नगरपालिकाओं) के बीच करों का वितरण,
 - उन करों, शुल्कों आदि का निर्धारण, जिन्हें स्थानीय निकायों को सौंपा जा सकता है या उनके द्वारा विनियोजित (Appropriated) किया जा सकता है, तथा
 - राज्य द्वारा स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान।
- राज्य वित्त आयोग से जुड़ी चिंताएं
 - कई राज्यों ने समय पर राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया है।
 - उदाहरण के लिए- 15वें वित्त आयोग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार केवल 15 राज्यों ने ही पांचवें या छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया था।
 - डेटा का अभाव: कई राज्य स्थानीय निकायों के बारे में सटीक डेटा प्रदान नहीं करते हैं। इस वजह से राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें तदर्थ यानी अस्थायी बनी रहती है।
 - एक्शन-टेकन रिपोर्ट (ATR) में देरी: राज्य अक्सर एक्शन-टेकन रिपोर्ट यानी सिफारिशों पर कार्रवाई का मसौदा तैयार करने में विफल रहते हैं। इन रिपोर्ट्स को राज्यपाल विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
 - राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोगों की बुनियादी सिफारिशों को भी अस्वीकार कर देती हैं। केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के मामलों में ऐसा नहीं होता है।
- राज्य वित्त आयोग में सुधार के उपाय
 - 15वें वित्त आयोग ने 2020 की रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्य वित्त आयोग से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले राज्यों को मार्च 2024 के बाद अनुदान जारी नहीं किया जाना चाहिए।
 - इस सिफारिश के बाद अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया था।

अन्य सुर्खियां



विश्व ऊर्जा रोजगार, 2024 रिपोर्ट

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा रोजगार, 2024 (World Energy Employment, 2024) रिपोर्ट जारी की।
- रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:
 - वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार ने 2023 में श्रम बाजार के व्यापक ट्रेड को पीछे छोड़ दिया।
 - स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र, रोजगार में वृद्धि का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है।
- रिपोर्ट में भारत से संबंधित मुख्य बिंदु:
 - भारत में ऊर्जा क्षेत्र में 8.5 मिलियन से अधिक लोग नियोजित हैं। यह 2023 में देश में रोजगार प्राप्त कुल 566 मिलियन लोगों का 1.5% है।
 - भारत का ऊर्जा क्षेत्र भी कई अन्य क्षेत्रों की तरह, अनौपचारिक श्रम पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
 - सरकारी पहलों की वजह से ऊर्जा क्षेत्र में, विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में कार्यबल बढ़ने की संभावना है। इससे रोजगार सृजन को और बढ़ावा मिलेगा।



ऑपरेशन सागर-मंथन

- हाल ही में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ऑपरेशन सागर-मंथन के तहत 700 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त किया है।
 - मेथामफेटामाइन अधिक प्रभावी एडिक्टिव ड्रग है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
- ऑपरेशन सागर मंथन के बारे में
 - शुरुआत: इसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के सहयोग से शुरू किया है।
 - ऑपरेशन के उद्देश्य:
 - समुद्री मार्गों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना;
 - राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटना;
 - 2047 तक 'नशा मुक्त भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करना।



एवियन बोटुलिज़्म

- राजस्थान में पक्षियों की सामूहिक मृत्यु के पीछे एवियन बोटुलिज़्म को कारण माना गया है।
- एवियन बोटुलिज़्म के बारे में
 - यह गंभीर न्यूरोमस्क्युलर बीमारी है।
 - बीमारी की वजह: बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पादित टॉक्सिन।
 - एवियन बोटुलिज़्म के प्रकोप में सहायक परिस्थितियाँ:
 - जल का अधिक तापमान;
 - एनोक्सिस (ऑक्सीजन रहित या कमी) परिस्थितियाँ;
 - अपघटित पादपों, शैवाल या पशु अपशिष्टों में बैक्टीरियल सबस्ट्रेट।
 - मनुष्यों और पालतू जानवरों में संक्रमण: संक्रमित मछली, पक्षी आदि खाने से।



कोदो मिलेट

- मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों की मौत की वजह कोदो मिलेट का सेवन हो सकता है।
- कोदो मिलेट (पस्यालम स्क्रोबिकुलटम) के बारे में
 - इसे भारत में कोदुरा और वरगु के नाम से भी जाना जाता है। यह कई आदिवासी समुदायों का मुख्य भोजन है।
 - गुण:
 - इसमें डायटरी फाइबर और आयरन जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी मौजूद हैं।
 - इसका सेवन अस्थमा, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा, मधुमेह, हृदय रोग के उपचार में और महिलाओं में रजोनिवृत्ति (Postmenopausal) में उपयोगी माना जाता है।
 - यह सूखा-सहिष्णु, उच्च उपज क्षमता, अधिक दिन तक भंडारण जैसे गुणों से युक्त है।
 - खेती के लिए आदर्श जलवायु: गर्म और शुष्क जलवायु। इसकी खेती मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र में की जाती है।
 - वर्षा के तुरंत बाद काटे गए कोदो को खाने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है।



भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India: PCI)

- हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारतीय प्रेस परिषद (PCI) की स्थापना की गई थी।
- भारतीय प्रेस परिषद (PCI) के बारे में
 - उत्पत्ति: इसे पहली बार पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों के बाद 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत स्थापित किया गया था।
 - 1975 में आपातकाल के दौरान इसे भंग कर दिया गया था। बाद में प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत 1979 में भारतीय प्रेस परिषद की पुनः स्थापना की गई थी।
 - उद्देश्य: भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखना।
 - संरचना: इसमें एक अध्यक्ष (आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश) और 28 सदस्य होते हैं।



वाल्मीकि टाइगर रिजर्व

- बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दुर्लभ 'कैट स्लेक' देखा गया।
 - सामान्य कैट स्लेक या बोइगा ट्राइगोनाटा, अन्य सर्प प्रजातियों की तुलना में बहुत कम विषैला होता है। सांप की इस प्रजाति को अत्यंत दुर्लभ भी माना जाता है।
- वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में
 - यह देश का 18वां टाइगर रिजर्व है और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है।
 - इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और 1990 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।
 - यह भारत में हिमालय तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करता है।
 - इससे होकर बहने वाली नदियाँ: गंडक, पंडई, मनोर, हरहा, मसान और भापसा।
 - जीव-जंतु: बाघ, भालू, तेंदुआ, भारतीय बाइसन, लकड़बग्घा, जंगली कुत्ते आदि।
 - वनस्पति: साल, सागौन, बांस, सेमल, खैर आदि।



चाबहार बंदरगाह

- विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री के साथ बैठक के दौरान अफगानिस्तान को चाबहार बंदरगाह तक पहुंच प्रदान करने की पेशकश की।
- चाबहार बंदरगाह के बारे में
 - अवस्थिति: यह ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है।
 - चाबहार परियोजना: इसमें दो अलग-अलग बंदरगाह हैं- शाहिद बेहिश्ती और शाहिद कलंतरी।
 - महत्त्व:
 - यह भारत को मध्य एशिया तक पहुंच का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। इस प्रकार भारत को अफगानिस्तान व मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान से होकर पहुंच प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
 - ज्ञातव्य है कि ईरान और भारत दोनों अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) परियोजना में चाबहार बंदरगाह की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं।



सेन्ना टोरा के पौधे

- तमिलनाडु वन विभाग मुदुमलाई टाइगर रिजर्व (MTR) में पाए जाने वाले आक्रामक सेन्ना टोरा पादप को हटाने का नवीन प्रयोग कर रहा है।
- सेन्ना टोरा के बारे में
 - मूल प्रजाति: दक्षिण और मध्य अमेरिका की मूल प्रजाति है। यह सूखे घास के मैदानों व क्षेत्रों में वृद्धि करता है।
 - खतरा: मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में मौजूद विस्तृत घास के मैदान को इस आक्रामक प्रजाति से खतरा है। इससे इस घास के मैदान पर निर्भर हाथियों, हिरणों और भारतीय गौर जैसे स्थानीय वन्यजीवों पर भी अस्तित्व संबंधी खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
- “आक्रामक प्रजाति” के बारे में
 - एक आक्रामक प्रजाति ऐसी प्रजाति होती है, जो एक नए परिवेश (जहां यह मूल निवासी नहीं होती) में पारिस्थितिक या आर्थिक नुकसान का कारण बनती है। ये स्थानिक वन्य जीवों व मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती हैं।
 - जैसे- लैंडाना कैमारा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा आदि।

सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व



बिरसा मुंडा (1875-1900)

- डाक विभाग ने जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया।
 - गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है।
- बिरसा मुंडा के बारे में
 - उनका जन्म 1875 में वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था
 - उन्हें ‘धरती आबा’ यानी ‘धरती पिता’ के नाम से भी जाना जाता है
 - मुख्य योगदान:
 - उन्होंने पारंपरिक आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित किया।
 - उन्होंने बिरसाई धर्म की नींव रखी। उनके अनुयायी बिरसा को “भगवान” कहते थे।
 - उन्होंने प्रार्थना करने, शराब से दूर रहने और ईश्वर में आस्था रखने के महत्त्व पर जोर दिया।
 - उन्होंने ब्रिटिश राज की भूमि अतिक्रमण और जबरन श्रम कराने की नीति के खिलाफ ‘उलगुलान’ यानी महान क्रांति या महान विद्रोह का नेतृत्व किया था।
 - मूल्य: जुनून, बलिदान, साहस, न्याय, नेतृत्व कौशल, आदि।



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



रांची